

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 882
12.12.2022 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण हेतु निधियों का आवंटन

882. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए आम बजट 2021 में निधि आवंटित की है और यदि हां, तो इस संबंध में आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष में बजट में उक्त श्रेणी में राजस्थान के प्रदूषित जिलों को भी सम्मिलित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क), (ख) और (ग) : भारत सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (15वां - एफसी) के मिलियन प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड (एमपीसीसीएफ) के तहत दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2217 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। निधियों के आवंटन और व्यय का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य-योजना के हिस्से के रूप में एनसीएपी के तहत शहरों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है और 'प्राण' पोर्टल <https://prana.cpcb.gov.in> पर अपलोड किया गया है।

राजस्थान राज्य के 5 गैर-अवमानक शहर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं। 3 शहर अर्थात् जयपुर, जोधपुर और कोटा 15वें एफसी एमपीसीसीएफ के तहत शामिल किए गए हैं और 2 शहर अर्थात् अलवर और उदयपुर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शामिल किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए रुपये 166.29 करोड़ रुपये राजस्थान के 5 शहरों को आवंटित किए गए हैं।

अनुबंध-1

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान XV वित्त आयोग के अनुदान के तहत शामिल किए दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को प्रदान की गई धनराशि का विवरण

राज्य	क्रम सं.	शहरी समूह (यू.ए.)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंवटित निधि (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	1	विजयवाडा यू.ए.	31	उपलब्ध नहीं
	2	विशाखापत्तनम	37	उपलब्ध नहीं
बिहार	3	पटना यू.ए.	103	117.4
	4	दुर्ग भिलाईनगर यू.ए.	26	उपलब्ध नहीं
छत्तीसगढ़	5	रायपुर यू.ए.	28	उपलब्ध नहीं
गुजरात	6	अहमदाबाद यू.ए.	92	0
	7	राजकोट यू.ए.	20	0.38
	8	सूरत यू.ए.	66	12.8
	9	वडोडरा यू.ए.	26	उपलब्ध नहीं
हरियाणा	10	फरीदाबाद	25	8.535
झारखंड	11	धनबाद यू.ए.	26	उपलब्ध नहीं
	12	जमशेदपुर यू.ए.	29	5.41
	13	रांची यू.ए.	25	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	14	बृहत बंगलौर यू.ए.	140	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	15	भोपाल यू.ए.	44	उपलब्ध नहीं
	16	ग्वालियर यू.ए.	26	उपलब्ध नहीं
	17	इंदौर यू.ए.	51	उपलब्ध नहीं
	18	जबलपुर यू.ए.	30	उपलब्ध नहीं

महाराष्ट्र	19	औरंगाबाद यू.ए.	16	9.47
	20	ग्रेटर मुंबई यू.ए.	246	3.19
	21	नागपुर यू.ए.	33	0
	22	नासिक यू.ए.	21	0.76
	23	पुणे यू.ए.	68	1.03
	24	वसई-विरार नगर	16	0
पंजाब	25	अमृतसर यू.ए.	19	8.69
	26	लुधियाना	26	10.18
राजस्थान	27	जोधपुर यू.ए.	31	1.58
	28	जयपुर	83	11.83
	29	कोटा	27	3.52
तमिलनाडु	30	चैन्ने यू.ए.	91	91
	31	मुदुरै यू.ए.	15	6.63
	32	तिरुचिरापल्ली यू.ए.	11	9.76
तेलंगाना	33	हैदराबाद यू.ए.	118	-
उत्तर प्रदेश	34	आगरा यू.ए.	45	35.82
	35	इलाहाबाद यू.ए.	31	38.79
	36	गाजियाबाद यू.ए.	61	39.78
	37	कानपुर यू.ए.	75	72.42
	38	लखनऊ यू.ए.	75	128.8
	39	मेरठ यू.ए.	36	20.66
	40	वाराणसी यू.ए.	37	12.58
पश्चिम बंगाल	41	आसनसोल यू.ए.	17	12.56
	42	कोलकाता	194	239.8
कुल			2217	904.38

उपलब्ध नहीं: डाटा उपलब्ध नहीं।

*पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अव्ययित निधि का उपयोग भी वर्ष 2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया है।